

[2023] 5 एस. सी. आर. 551

जीनी धनराजगीर और ए. एन. आर.

बी.

शिवू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 3758 - 3796 2023 का)

16 मई, 2023

[ए. एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एस। 47 , ऑर्डर XXI आर। 97

फरमानों का निष्पादन-डिक्री धारक या खरीदार को कब्जे के वितरण का विरोध-मूल वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ अधिकार की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया-वादी के पक्ष में मुकदमा घोषित किया गया और प्रतिवादियों ने वादी को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में रखने का निर्देश दिया-अपील में, डिक्री को आंशिक के बदले में प्रतिवादियों को मुआवजे का भुगतान करने की सीमा तक संशोधित किया गया-प्रतिवादी नं। 1 और उसके बाद, प्रतिवादी रिक्त स्थान को समर्पण कर देंगे

संपत्ति का कब्जा-वादी के अपीलार्थी बेटे और बेटे द्वारा निष्पादन आवेदन-निष्पादन न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों द्वारा दायर आपत्तियां, जिन्होंने प्रतिवादी नं। 1 रखरखाव योग्य होना और अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक समझना-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: प्रत्यर्थियों द्वारा डिजिटल संपत्ति में उनके संबंधित शेयरों के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज के बारे में दावा, जैसा कि उठाया गया है, नहीं किया जा सकता है

श्रेसहोल्ड पर बाहर फेंक दिया गया क्योंकि आवेदन यू/ऑर्डर का विरोध करना उनके अधिकारों के भीतर है। XXI आर। 97 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर

-

चूँकि साक्ष्य को उसके समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, इसलिए निष्पादन न्यायालय ने आपत्तियों को इस मामले में बनाए रखने योग्य ठहराते हुए उचित ठहराया।

इस अर्थ में नहीं कि उनके खिलाफ डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस अर्थ में कि जांच करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था, और पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के लिए मामले को पोस्ट करना-आर में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर। 101 , निष्पादन न्यायालय आर द्वारा अनिवार्य तरीके से आगे बढ़ेगा। 98 - इस प्रकार, चुनौती के तहत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-अपीलार्थियों के आवेदन से निपटने के लिए निष्पादन न्यायालय यू/ऑर्डर XXI आर। 97 उत्तरदाताओं द्वारा अपने गुण-दोष पर उठाई गई आपत्तियों के साथ-साथ-अपीलकर्ता दो दशकों से अधिक समय से डिक्री के फल से वंचित हैं, यह न्यायसंगत और उचित होगा।

[2023] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित है कि निष्पादन न्यायालय इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करे।

भारत का संविधान: कला. 136 - के आदेश के विरुद्ध सीधे इस न्यायालय के समक्ष आने वाले अपीलार्थी के अधीन अनुमति देने की शक्ति

ऐसे आदेशों को उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी चुनौती के अधीन किए बिना निष्पादन न्यायालय-की अनुमति-आयोजित की गई: इस न्यायालय को ऐसे मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए कि वादियों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए कूदना, छोड़ना और कूदना नहीं चाहिए क्योंकि उपचार त्वरित और अधिक प्रभावी है-सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकाधिकार में विशेष अनुमति याचिकाओं पर सीधे ट्रिब्यूनल/अदालतों के आदेशों से विचार करता है, बिना उच्च न्यायालय से केवल उन मामलों में संपर्क किया गया है जहां सामान्य महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

इसमें शामिल या जहां इसी तरह का कोई मुद्दा विचाराधीन है, यह न्यायालय 'विशेष अवकाश' अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष को उपलब्ध उपचार-वैकल्पिक उपचार को दरकिनार करने की अनुमति नहीं देगा।

अपीलों और अवमानना याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 सी. पी. सी. की धारा 47, जो फरमानों के निष्पादन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है, यह आदेश देती है कि -

डिक्री को निष्पादित करने वाला न्यायालय उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का निर्धारण करेगा।

डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि के संबंध में मुकदमे के पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच और यह कि ऐसे प्रश्नों पर एक अलग मुकदमे में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। निष्पादन पर अनन्य अधिकारिता प्रदान करने का क्या उद्देश्य है

न्यायालय अनावश्यक और अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए है और चर्चा के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का त्वरित निपटान करना।

डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि के संबंध में। क्या कोई प्रतिरोध या बाधा होनी चाहिए?

एक अदालत द्वारा बनाई गई डिक्री के उचित निष्पादन में बाधा डालना

सक्षम अधिकारिता, के नियम 97, 101 और 98 के प्रावधान आदेश XXI निष्पादन न्यायालय को अंतर-स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

कानून ई-धारक और निष्पादन कार्यवाही में तीसरे पक्ष के अनुसार विवादास्पद मुद्दों से बचने के लिए पक्षकारों को संस्था में लाने के लिए प्रेरित करके मुकदमेबाजी का विस्तार

स्वतंत्र सूट। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आदेश XXI सी. पी. सी. के नियम 97 से 106 में उप-शीर्षक "प्रतिरोध जीनी धनराजगीर और ए. एन. आर". के तहत प्रावधान हैं।

वी. शिवू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी।

डिक्री धारक या खरीदार को अधिकार की डिलीवरी को अपने आप में एक पूर्ण संहिता माना गया है। आदेश XXI के नियम 97 से 103 मुकदमे के पक्षों के साथ-साथ निष्पादन के लिए रखी गई डिक्री के लिए एक अजनबी दोनों को एकमात्र उपाय प्रदान करते हैं। [पैरा 17] [565-एफ-जी; 566-ए-सी]

1.2 आदेश XXI के नियम 102 के आदेश के संदर्भ में, नियम 98 और 100 प्रतिरोध पर लागू नहीं होंगे या

के कब्जे के लिए एक डिक्री के निष्पादन में बाधा

एक व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति जिसे निर्णय-देनदार ने उस मुकदमे की स्थापना के बाद संपत्ति हस्तांतरित की है जिसमें डिक्री पारित की गई थी। [पैरा 23] [567-ई]

1.3 यह निवेदन कि उत्तरदाता कुछ देर के लिए विचाराधीन हैं

हस्तांतरणकर्ताओं के लिए, आई. एस. पेडेंस का सिद्धांत लागू होता है, और नियम 102 की स्पष्ट शर्तों को देखते हुए, आपत्तियां बनाए रखने योग्य नहीं थीं; इसलिए, उत्तरदाता नियम 98 के संदर्भ में अपने दावों का निर्णय लेने के संरक्षण के हकदार नहीं हैं, हालांकि पहली बार में आकर्षक हैं, लेकिन यहां प्राप्त होने वाले विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए महत्वहीन हो जाते हैं। यदि, वास्तव में, उस समय के दौरान मुकदमा खारिज होने के बाद स्थानांतरण हुए हैं जब कोई नहीं था

लंबित रहने तक, निष्पादन न्यायालय के लिए इस प्रश्न का निर्धारण करना सबसे उपयुक्त होगा कि क्या प्रतिवादी द्वारा किए गए स्थानान्तरण में से कोई भी नहीं है। 3 उत्तरदाताओं को नियम 102 आकर्षित करेगा। इसमें वास्तव में पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अभ्यास शामिल होगा और केवल इसलिए कि मुकदमा अंततः 21 अक्टूबर 2000 को घोषित किया गया था और अंततः इस न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि में मामूली संशोधन के साथ बरकरार रखा गया था, जो उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को योग्यता से रहित होने के रूप में खारिज करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं होगा। [पैरा 24 और 25] [567-एफ-जी; 568-ए-बी]

1.4 5 अप्रैल 2018 के अप्रत्यासित आदेश को ध्यान में रखते हुए निष्पादन न्यायालय का विवादित आदेश उच्च न्यायालय ने आपत्तियों को बनाए रखने योग्य पाया है, कम से कम एक जांच की आवश्यकता है। तथ्यों पर, हस्तक्षेप के योग्य इस तरह के आदेश में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है। [पैरा 27] [568-ई]

1.5 केवल इसलिए कि इस न्यायालय ने 11 फरवरी 2014 की पहली अपीलिय डिक्री में हस्तक्षेप नहीं किया था, एस. सी. आर. के लिए कोई आधार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 101 द्वारा विचार किया गया। यह न्यायालय अपने दृष्टिकोण की अनुमति नहीं देगा। 13
अक्टूबर 2014 के आदेश को डिक्री धारकों और अजनबियों/तीसरे पक्षों के बीच विवादों को समाप्त करने के रूप में माना जाएगा, जो इससे पहले नहीं थे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय की गरिमा, प्रतिष्ठा और महिमा को बनाए रखना है, फिर भी, केवल इसलिए कि एक ओर अपीलार्थियों और प्रतिवादी संख्या के बीच का मुद्दा है। 2

और दूसरी ओर 3 ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, वही इस न्यायालय के लिए अपीलार्थियों के तर्क को बनाए रखने के लिए कोई औचित्य, बहुत कम पर्याप्त औचित्य, वहन नहीं करेगा, जो आदेश XXI के नियम 97 से 103 तक अजनबियों/तीसरे पक्षों को प्रदान करने वाले मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के बजाय तोड़-फोड़ का प्रभाव डालता है।

अधिकार की वसूली के लिए डिक्री से बाध्य नहीं। प्रत्यर्थियों द्वारा डिक्रीटल संपत्ति में उनके संबंधित शेयरों के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज के बारे में दावा, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया है, को सीमा पर नहीं फेंका जा सकता है क्योंकि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आदेश XXI नियम 97, सी. पी. सी. के तहत आवेदन को चुनौती देना उनके अधिकारों के भीतर है। चूंकि उसके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, इसलिए निष्पादन न्यायालय इस स्तर पर आपत्तियों को बनाए रखने योग्य ठहराने के लिए इस अर्थ में न्यायोचित था कि उनके खिलाफ डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस अर्थ में कि एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था ताकि जांच की जा सके और पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के लिए मामले को पोस्ट किया जा सके। नियम 101 में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर, निष्पादन न्यायालय नियम 98 द्वारा अनिवार्य तरीके से आगे बढ़ेगा। [पैरा 28] [568-ई-एच; 569-ए-सी]

1.6 इस न्यायालय को ऐसे आदेश के बिना निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपीलों पर विचार नहीं करना चाहिए

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा किसी भी चुनौती के अधीन

अदालत। वादियों को त्वरित और अधिक प्रभावी उपचार की तुलना में बिना किसी बेहतर कारण के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए कूदना, छोड़ना और कूदना नहीं चाहिए। अभ्यास के रूप में, सर्वोच्च

अदालत अपने विवेकाधिकार पर विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करती है

उच्च न्यायालय के बिना सीधे न्यायाधिकरणों/न्यायालयों के आदेशों से केवल उन मामलों में संपर्क किया गया है जहां सामान्य महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं या जहां समान हैं।

यह मुद्दा (उच्चतम न्यायालय) के विचार के लिए लंबित है।

जीनी धनराजगीर और ए. एन. आर. वी. शिवू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी।

अनुच्छेद 136 के तहत छुट्टी देने की शक्ति अपने आप में विवेकाधीन होने के कारण, यह न्यायालय 'विशेष छुट्टी' अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष को इस स्तर पर उपलब्ध उपचार को दरकिनार करने की अनुमति नहीं देगा।

दोनों स्थितियों को संतुष्ट किए बिना उच्च न्यायालय। वास्तव में, यह ऐसा कोई मामला नहीं है। [पैरा 29] [569-डी-एफ] 1.7 चुनौती के तहत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसे बरकरार रखा जाता है। निष्पादन न्यायालय आगे बढ़ेगा

आदेश XXI सी. पी. सी. के नियम 97 के तहत अपीलार्थियों के आवेदन के साथ-साथ उत्तरदाताओं द्वारा अपने गुण-दोष पर और किसी से प्रभावित हुए बिना उठाई गई आपत्तियों से निपटना। इस आदेश में किया गया अवलोकन जो केवल वर्तमान अपीलों के निपटारे के लिए आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता दो दशकों से अधिक समय से डिक्री के फल से वंचित हैं, निष्पादन न्यायालय से अनुरोध करना उचित और उचित होगा कि वह बिना अनुमति दिए विवादास्पद मुद्दों पर कानून के अनुसार जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े।

किसी भी पक्ष के लिए अनावश्यक स्थगना। [पैरा 30-32] [569 G-H; 570-A-B]

1.8 प्रतिवादी को दंडित करने के लिए अपीलार्थियों द्वारा शुरू की गई अवमानना याचिका संख्या। 2 और 3 विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 24344/2014 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए, इस स्तर पर, जीवित नहीं है; इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। [पैरा 33] [570-सी]

राज दुर्भुगा के महाप्रबंधक, कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत बनाम महाराजा कुमार रामपुत सिंह (1871-72) 14 मू आई ए 605; कुर जंग बहादुर बनाम बैंक ऑफ अपर इंडिया लिमिटेड. लखनऊ ए. आई. आर. 1925 अवध 448; मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम. कलकत्ता निगम ए. आई. आर 1966 एस. सी. 529: [1966] एस. सी. आर. 543; उषा सिन्हा बनाम दीना राम (2008) 7 एस. सी. सी. 144: [2008] 4 एस. सी. आर. 1192; न्यासी मंडल बनाम निखिल गुप्ता (2015) 10 एस. सी. सी. 1339; श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम एस. ओमेश मिश्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 794; फर्म गणपत राम राजकुमार बनाम कालू राम और अन्य। (1989) पूरक 2 एस. सी. सी. 418: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 223; चीरनथूडिका अहमदकुट्टी और अन्न। बनाम।

परम्बुर मरियाकुट्टी उम्मा और अन्य। (2000) 2 एससीसी 417 [2023] 5 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

: [2000] 1 एससीआर 725; ब्रह्मदेव चौधरी बनाम

ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल (1997) 3 एस. सी. सी. 694: [1997] 1

एस. सी. आर. 463; टी. विजेंद्रदास और अन्न। बनाम एम. सुब्रमण्यन और

ओआरएस। (2007) 8 एससीसी 751: [2007] 10 एस. सी. आर. 880; आई.
टी. आई. लिमिटेड

वी. सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क लिमिटेड (2002)
5 एससीसी 510 [2002] 3 एससीआर 1122; कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर

कंपनी वी। आयकर निदेशक, बेंगलोर (2012)

भंवर लाल बनाम सत्यनारायण (1995) 1 एस. सी. सी. 6: [1994]
4 पूरक। एस. सी. आर. 208; नूरदुद्दीन बनाम डॉ. के. एल. आनंद (1995)

1 एससीसी 242: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 322; बाबूलाल बनाम राज

कुमार और ओआरएस। (1996) 3 एससीसी 154: [1996] 2 एससीआर 763;

सिल्वरलाइन फोरम प्रा. लिमिटेड वी. राजीव ट्रस्ट एंड एन. आर. (1998)

3 एससीसी 723: [1998] 2 एस. सी. आर. 587 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

ए. आई. आर. 1925 अवध 448

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1966] एससीआर 543

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2008] 4 एससीआर 1192

पैरा 11 (

संदर्भित किया गया है

(2015) 10 एस. सी. सी. 1339

पैरा 11 (

संदर्भित किया गया है

[1989] 1 पूरक। एससीआर 223

पैरा 11 (

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 एससीआर 725

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1997] 1 एससीआर 463

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2007] 10 एससीआर 880

संदर्भित किया गया है

पैरा 13 (

[2002] 3 एससीआर 1122

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2012] 7 एससीआर 187

पैरा 13

संदर्भित किया गया है

[2019] 2 एससीआर 664

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1994] 4 पूरक। एससीआर 208

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1994] 4 पूरक। एससीआर 322

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[1996] 2 एससीआर 763

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1998] 2 एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 22 जीनी धनराजगीर और ए. एन. आर. वी. शिबू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 3758

3796 2023 तक।

प्रधानाचार्य के 29.06.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

उप-न्यायाधीश, कोर्टायम, ई. ए. संख्या में केरल। 299 , 300 , 302 , 303 , 304 , 305 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 335 , 344 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 364 , 365 2017 का और 2018 का 127।

के साथ

2014 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 24344 में 2018 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 2091।

श्याम दीवान, अरविंद मिनोचा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जॉर्ज चेरियन,

मयंक क्षीरसागर, सुश्री आभा गोयल, सुश्री अंशुला लारोइया, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

वी. चितमबरेश, वरिष्ठ अधिवक्ता। , टी. जी. नारायणन नायर, एम. टी. जॉर्ज

श्रीमती सूसी अब्राहम, जॉन्स जॉर्ज, सी. वेणुगोपाल, सुश्री सोनल गुप्ता, के. वी. मोहन, सुश्री टेसी वर्गीज, सुश्री तातवेंदर कौर, के. के. विनोश, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था दीपांकर दत्ता, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. डेढ़ सदी से भी पहले, प्रिवी काउंसिल (राइट ऑन के माध्यम से बोल रही थी। सर जेम्स कोलविल) द जनरल मैनेजर में

राज दुर्भुगा के, वार्ड बनाम महाराजा कुमार रामपुत सिंह 1 के न्यायालय के तहत, ने शोक व्यक्त किया कि भारत में वादियों की कठिनाइयाँ वास्तव में तब शुरू होती हैं जब वे एक डिक्री प्राप्त करते हैं। उपरोक्त अवलोकन का संदर्भ कुएर जंग बहादुर बनाम बैंक ऑफ अपर मामले में अवध न्यायिक आयुक्त न्यायालय के फैसले में भी पाया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतें कि न्यायालय की प्रक्रिया और प्रक्रिया के कानूनों का निर्णय-देनदारों द्वारा इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया गया था कि वे उन लेनदारों को धोखा देने में अदालतों को सहायक बना सकें, जिन्होंने अपने अधिकारों के अनुसार फरमान प्राप्त किए थे। 1 (1871-72) 14 मू आई ए 605 2 ए. आई. आर 1925 अवध 448 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. समय के भारी अंतराल के बावजूद, हम रह गए हैं

प्रिवी काउंसिल के अवलोकन पर आश्चर्यचकित जो भविष्यसूचक साबित हुआ है। यह अवलोकन अभी भी वर्तमान समय में सही है और यह मामला डिक्री धारकों के संकट के मामलों से अलग नहीं है, जबकि वे सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी न्यायालयों द्वारा पारित वैध और बाध्यकारी फरमानों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। डिक्री धारकों के दृष्टिकोण से देखने पर स्थिति वास्तव में परेशान करने वाली है, लेकिन कानून, जैसा कि यह है, को प्रभावी बनाना होगा चाहे अदालत को परिणाम पसंद आए या नहीं। मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम। कलकत्ता निगम 3, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

न्यायालय के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए मानता है।

4. श्रीमती तारा चेरियन ("श्रीमती चेरियन", इसके बाद) की बेटी और बेटे, अपीलकर्ताओं द्वारा इन दीवानी अपीलों में चुनौती प्रधान उप-न्यायाधीश, कोट्टायम, ("निष्पादन न्यायालय", इसके बाद) दिनांक 29 जून, 2018 के सामान्य अंतरिम आदेश के लिए है। निष्पादन न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सी. पी. सी.", इसके बाद) के आदेश XXI नियम 97 के साथ पठित धारा 47 के तहत एक निष्पादन आवेदन को जब्त कर लिया गया था, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा 21 अक्टूबर, 2000 ("डिक्री", इसके बाद) के डिक्री को लागू करने और यहाँ ("उत्तरदाताओं", इसके बाद) प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं द्वारा रखे गए प्रतिरोध को हटाने की मांग की गई थी। विवादित आदेश द्वारा, निष्पादन न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर कई आपत्तियों को बनाए रखने योग्य माना और साक्ष्य की उचित रिकॉर्डिंग के बाद, अपने गुण-दोष पर निर्णय लेना आवश्यक समझा।

5. उठाये गए विवाद की प्रकृति और विस्तार को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी

अपीलों और प्रतिद्वंद्वी विवादों को किसी भी बड़ी गहराई में बार में आगे बढ़ाना; हालाँकि, चूंकि पक्षों ने हमें विस्तार से संबोधित किया है, इसलिए हम आवश्यक तथ्यों का संक्षेप में वर्णन करने और संदर्भ देने का प्रस्ताव करते हैं

इस तरह के दावों पर हमारे निष्कर्षों को दर्ज करने से पहले पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी दावे।

6. कार्यवाही के दो सेटों से उत्पन्न होने वाले बुनियादी तथ्य, जिन्हें हम वर्तमान में विज्ञापित करेंगे, आपस में जुड़े हुए हैं; इसलिए, यह माना जाता है

प्रशंसा की सुविधा के लिए उसी को विच्छेदित करना उचित है।

7. तथ्यात्मक मैट्रिक्स का पहला भाग यह है:

मूल वादी के रूप में श्रीमती चेरियन ने ओएस नंबर 28/की स्थापना की।

ए।

1987 (" मुकदमा ", इसके बाद) अन्य बातों के साथ-साथ श्री वी. टी.

3 एयर 1966 एससी 529 एन. आर. ए. जे. जी. आई. आर. और ए. एन. आर.

वी. शिवू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी। [दीपांकर दत्त, जे।]

मैथ्यू [प्रतिवादी नं. 1] , उसके बेटे [प्रतिवादी नं. 2 , श्री थॉमस मैथ्यू ("श्री थॉमस", इसके बाद) और प्रतिवादी नं. 3 , श्री अब्राहम मैथ्यू ("श्री अब्राहम", इसके बाद) और श्री मैथ्यू के सहायक प्रतिवादी नं. 4 , श्री के. टी. गाँव में 2.81 एकड़ से अधिक भूमि के संबंध में श्रीमती चेरियन के अधिकार की घोषणा के लिए जोसेफ ("प्रतिवादी", जहाँ भी सामूहिक रूप से संदर्भित किया जाता है, इसके बाद)

नाट्टकोम, कोट्टायम, तालुक, कोट्टायम जिला, केरल (" सूट संपत्ति " , इसके बाद), और प्रतिवादियों से अपने लाभ के साथ कब्जे की वसूली।

श्रीमती चेरियन ने तर्क दिया कि सूट संपत्ति के कार्यवाहक श्री मैथ्यू ने अपने मृत पति से इसे खरीदने का इरादा किया था, बिक्री पूरी नहीं हुई थी क्योंकि शेष राशि का भुगतान अभी भी किया जाना था, और अंतरिम में प्रतिवादियों ने सूट संपत्ति पर निर्माण किया था। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वे मौखिक पट्टे के माध्यम से सूट संपत्ति के संबंध में किरायेदार थे

श्रीमती चेरियन के मृत पति और उनके साथ समझौता

श्री मैथ्यू का 18 जनवरी 1998 को निधन हो गया और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रही जिसमें उनके बेटे श्री थॉमस और श्री अब्राहम ने अपील को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 1998 को ए. एस. नं. 27/1991 की अनुमति दी और राय दी कि प्रतिवादी कार्यकाल तय करने के हकदार नहीं थे। मुकदमे को अन्य मुद्दों पर निर्णय के लिए निचली अदालत में भेज दिया गया था।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. एम. ए. की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

एफ.

नं. एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश के खिलाफ एक अपील होने के नाते, 13 दिसंबर 1999 को इसे खारिज कर दिया गया और पुष्टि की गई कि श्री मैथ्यू ने केवल सूट संपत्ति का कार्यवाहक रहा।

रिमांड पर, 21 अक्टूबर 2000 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया था।

जी।

श्रीमती चेरियन और प्रतिवादियों के पक्ष में श्रीमती चेरियन को सूट संपत्ति के कब्जे में रखने का निर्देश दिया गया। श्री थॉमस और श्री अब्राहम ने ए. एस. नं. 219/2001 दाखिल किया।

एच.

उच्च न्यायालय के समक्ष 11 फरवरी 2014 को इसे आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी गई थी कि डिफेंडी को संशोधित किया गया था जिसके तहत श्रीमती चेरियन को रु। 25,99,250 आंशिक के बदले में मुआवजे के रूप में श्री मैथ्यू द्वारा भुगतान किए गए खरीद विचार का भुगतान, जिसके बाद प्रतिवादी खाली कब्जे को सौंप देंगे

उसे अवैध संपत्ति।

11 फरवरी 2014 का आदेश इससे पहले जारी किया गया था।

आई.

एस. एल. पी. में श्री थॉमस और श्री अब्राहम द्वारा यह न्यायालय (ग) सं. 24344/2014। 13 अक्टूबर 2014 को, इस न्यायालय ने उक्त याचिका का निपटारा करते हुए मुआवजे को मामूली रूप से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। 30,00, 000.00 . अपीलार्थियों को शेष क्षतिपूर्ति जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद प्रतिवादियों को अपीलार्थियों को अवैध संपत्ति का कब्जा सौंपना आवश्यक था।

अन्यथा अबाधित रखा जाता है।

8. यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स का एक हिस्सा होने के कारण, हम दूसरे भाग पर ध्यान देते हैं। यह के. एल. आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही के साथ शुरू होता है।

एस. एम. सं. 107/1992 और भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष 55-56/1989। 23 जनवरी 1993 को भूमि न्यायाधिकरण ने श्री मैथ्यू को एस. एम. सं. <आई. डी. 1 में एक खरीद प्रमाण पत्र जारी किया,

जिसके तहत श्री मैथ्यू को खेती करने वाले किरायेदार का दर्जा दिया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती चेरियन को नोटिस पर रखा गया था लेकिन उन्होंने अंततः कार्यवाही का विरोध नहीं किया। खरीद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, श्री मैथ्यू द्वारा कुछ प्रत्यर्थियों को अचल संपत्ति के पार्सल बेचे गए। कुछ अन्य उत्तरदाताओं को एस. एम. सं. 55/1989 और एस. एम. सं. 56/1989 में खरीद प्रमाण पत्र भी जारी किए गए थे, जो सूट की स्थापना के बीच की अवधि के दौरान और 21 अक्टूबर 2000 को इसके आदेश दिए जाने से बहुत पहले थे।

एन. आर. राजगीर और ए. एन. आर. वी. शिवू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी। [दीपांकर दत्त, जे।] निम्नलिखित बाद की घटनाएं और भी महत्वपूर्ण हैं -

मामला:

27 मई 2017 को ई. पी. संख्या 379/में निष्पादन न्यायालय

अपीलार्थियों को अधिकार। इसके बाद, विरोध करने वालों के रूप में कुछ उत्तरदाताओं ने मुख्य निष्पादन कार्यवाही में डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जताते हुए और कब्जा देने से इनकार करते हुए कई आपत्तियां दायर कीं।

27 मई 2017 को अदालत। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। 5 अप्रैल 2018 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि

प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आपत्तियों पर अपीलार्थियों की दलीलों पर विचार करने और उसी पर निर्णय लेने के लिए निष्पादन न्यायालय

30 जून 2018 को या उससे पहले।

एक विवादित सुनवाई के बाद, प्रधान उप-न्यायाधीश, कोर्टायम ने, निष्पादन न्यायालय होने के नाते, 29 जून 2018 को वर्तमान विवादित अंतरिम आदेश पारित किया।

श्री दीवान, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील

टोपी:

एस. एल. पी. में दलीलें। (ग) श्री थॉमस और श्री अब्राहम द्वारा दायर सं. 24344/2014 में इस बात का कोई खुलासा नहीं किया गया है कि किसी और के पास अवैध संपत्ति है। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों का आचरण निचली अदालत द्वारा पारित फरमान और इस अदालत तक और उसके द्वारा इसकी पुष्टि की जानबूझकर अवज्ञा में था। उत्तरदाताओं के पास [2023] 5 एस. सी. आर. में कोई अधिकार नहीं थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिक्रिटल संपत्ति और इसलिए इस मामले में डिक्री का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है जो दो दशकों में बनाया गया था

पीछे की ओर।

उत्तरदाताओं की दलीलें खरीद पर आधारित हैं।

बी।

श्री द्वारा प्राप्त एस. एम. सं. 197/1992 होने का प्रमाण पत्र।

मैथ्यू, भूमि न्यायाधिकरण, कोर्टायम से। हालाँकि, उत्तरदाताओं के पास व्यक्ति के रूप में उक्त संपत्तियों का कोई अधिकार नहीं था जिनसे यह उपाधि प्राप्त होती थी, अर्थात् श्री मैथ्यू का स्वयं इस अवैध संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था।

जिन व्यक्तियों पर अलग-अलग भूखंड खरीदने का आरोप है

सी।

श्री मैथ्यू की अवैध संपत्ति ने निष्पादन न्यायालय में अपनी आपत्ति याचिकाओं के साथ स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

आपत्तियाँ तुच्छ हैं और विचारणीय नहीं हैं।

डी।

एसएलपी (सी) सं. 24344/2014 में 13 अक्टूबर 2014 के इस न्यायालय के आदेश के आलोक में, जिसने इन कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया था, प्रत्यर्थियों के आचरण का प्रभाव पड़ता है

इस तरह के आदेश को रद्द करना।

अपीलार्थी पहले ही रुपये जमा कर चुके थे। 30,00,000 के साथ

ई.

13 अक्टूबर 2014 को इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निचली अदालत, और यह कि उत्तरदाता आनंद ले रहे थे
दिए बिना डिक्रिटल संपत्ति

कब्जा

अपीलार्थी।

संपत्ति

हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के अनुसार,

एफ.

उपर्युक्त स्थानान्तरण पर दंड का प्रभाव पड़ता है और यह अनुज्ञेय नहीं था; इसके अलावा, के आदेश XXI के नियम 102 को देखते हुए

सी. पी. सी., उसके नियम 98 और 100 को आकर्षित नहीं किया जाएगा और निष्पादन न्यायालय ने स्वयं को गलत तरीके से निर्देशित किया

प्रत्यर्थियों की आपत्तियाँ बनाए रखने योग्य हों।

11. श्री दीवान ने समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया

विवाद:

उषा सिन्हा बनाम दीना राम 4, जहाँ यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ,

ए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक लटकते हुए हल्के खरीदार को खरीदार के अधिकारों के रूप में प्रतिरोध करने या बाधा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं था एक डिक्री में स्पष्टीकृत नहीं किया गया था।

:)

7 एस. सी. सी. 144 धनराजगीर और ए. एन. आर. वी. शिबू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी। [दीपांकर दत्त, जे।]

न्यासी मंडल बनाम निखिल गुप्ता 5, जहाँ यह न्यायालय

बी।

अवरोधकों को सौंपने के निर्देश जारी किए

उस मामले में याचिकाकर्ता को अधिकार जहां तीन दशकों की मुकदमेबाजी के बाद बेदखली की डिक्री प्राप्त की गई थी।

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड

सी।

इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदेश XXI नियम 97 एक डिक्री धारक को किसी भी मामले में शिकायत करने के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है।
अचल संपत्ति के कब्जे में प्रतिरोध या बाधा और उस नियम 102 ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम 98 और

100 उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां हस्तांतरणकर्ता द्वारा निष्पादन में प्रतिरोध या बाधा की पेशकश की गई थी।
जहाँ
संपत्ति को किसी निर्णय देनदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को एक वाद की स्थापना के बाद हस्तांतरित किया गया था जिसमें -

निष्पादित किए जाने का आदेश पारित किया गया।

डी।

फर्म गणपत राम राजकुमार बनाम कालू राम और अन्य 7,

जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन न करना,

आदेश से निराशा नहीं होनी चाहिए।

12. श्री दीवान, तदनुसार, मामले के न्याय की अपील की

आक्षेपित आदेश को दरकिनार करते हुए और अपीलार्थियों को डिफ्रिटल के कब्जे में रखने के लिए ए. टी. आई. एन. जी. अदालत को निर्देश देते हुए

प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई बाधाओं को दूर करने के बाद।

13. इसके विपरीत, श्री चितमबरेश, विद्वान वरिष्ठ वकील

उत्तरदाताओं के लिए रिंग ने तर्क दिया कि:

ए। श्री मैथ्यू पूरी अवैध संपत्ति के किरायेदार थे।

और इसके एक हिस्से पर उन्होंने श्री थॉमस और श्री अब्राहम मैथ्यू के साथ मिलकर इमारतों का निर्माण किया था। भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष एस. एम. नं. <आई. डी. 1 में, श्रीमती चेरियन एक पक्षकार थीं, फिर भी, उन्होंने श्री मैथ्यू के पक्ष में जारी किए जाने के बाद खरीद प्रमाणपत्र को चुनौती नहीं दी। इसके अलावा, भूमि न्यायाधिकरण द्वारा कुछ प्रत्यर्थियों को दो अन्य खरीद प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

एस. एम. नंबर। 55 और 56/1989।

-) एससीसी ऑनलाइन एससी 794 +) पूरक 2 एस. सी. सी. 418 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चीरान्थूडिका में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में

बी।

अहमदकुट्टी और अन्न। बनाम परम्बुर मरियाकुट्टी

उम्मा और ओआरएस 8, जहां यह माना गया था कि की अनुपस्थिति में

खरीद की सत्यता पर संदेह करने के लिए कोई भी सामग्री

कानून के अनुसार उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए थे, यह प्रस्तुत किया गया था कि के. एल. आर. की धारा 72 के तहत स्वतः संज्ञान कार्यवाही में जारी खरीद प्रमाण पत्र

अन्य बातों के साथ-साथ श्री मैथ्यू के पक्ष में किया गया कार्य उनकी उपाधि का निर्णायक प्रमाण था और तब से वही बना हुआ है।

बिना चुनौती दिए, रेस जुडिकाटा के रूप में काम करेगा। प्रतिवादियों ने विरोध करने वालों के रूप में शीर्षक स्थापित किया था, स्वतंत्र

सी।

निर्णय-देनदार, और यह कि उनकी आपत्ति योग्य है

निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना।

इसके अलावा, निष्पादन न्यायालय ने केवल विरोधियों को ही अभिनिर्धारित किया था '

डी।

आवेदनों को बनाए रखने योग्य होना चाहिए; ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को तब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब गुण-दोष पर निर्णय दिया जाना बाकी था। ब्रह्मदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल ',

ई.

इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि एक दावा इसके अनुसार दायर किया गया है

आदेश XXI नियम 97 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 47 है

अधिकार के स्वतंत्र होने के बावजूद बनाए रखने योग्य

निर्णय-देनदार।

टी विजेंद्रदास और अन्न में निर्णय। बनाम एम.

एफ.

सुब्रमण्यन और अन्य ने माना है कि यदि कोई निर्णय या

आदेश धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था, तो वही एक शून्य है; और चूंकि ए. एस. सं. 27/1991 में निर्णय श्री मैथ्यू के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना प्राप्त किया गया था, क्योंकि इस कारण से, कार्यवाही धोखाधड़ी और अकृतता से दूषित हो जाती है

दमनकारी सच्चाई के कारण।

आई. टी. आई. लिमिटेड बनाम सीमेंस सार्वजनिक संचार

जी।

नेटवर्क लिमिटेड 1 1, इस न्यायालय ने नोट किया था कि विशाल शक्तियों के बावजूद उसे सीधे अपील पर विचार करना था, वादियों को अधिक प्रभावी उपचार की संभावित उम्मीद में अन्य उपलब्ध उपायों को दरकिनार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

7) 8 एस. सी. सी. 751

2) 5 एस. सी. सी. 510 जीनी धनराजगीर और ए. एन. आर. वी. शिवू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी। [दीपांकर दत्त, जे।]

सीधे इस न्यायालय में पहुँचने में अपीलार्थियों का आचरण

एच.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पुनरीक्षण या अपीलीय क्षेत्राधिकार का आह्वान किए बिना

उचित मंच निर्णय के आधार पर आलोचना के लिए खुला है

कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर कंपनी बनाम। निदेशक आयकर, बेंगलोर 1 2, जहां इस न्यायालय ने राय दी कि विशेष अनुमति देते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधिकार का दायरा ऐसा था कि केवल सामान्य महत्व के एक महत्वपूर्ण प्रश्न या इस न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब अनुच्छेद 226 और/या 227 के तहत उपचार उपलब्ध थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हीं आधारों पर।

लिस पेंडेंस सिद्धांत के अनुप्रयोग का प्रश्न करता है

आई.

तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि बिक्री लेनदेन तब प्रभावित हुए थे जब कोई एल. आई. एस. लंबित नहीं था।

14. उपरोक्त दलीलों पर विराम लगाते हुए, श्री चितमबरेश ने आग्रह किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है और

निष्पादन न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए।

15. एकमात्र मुद्दा जो हमें इस स्तर पर तय करने का काम सौंपा गया है, वह है -

क्या अपील के तहत सामान्य आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है

या नहीं।

16. हमारे सुविचारित विचार में, एक से अधिक कारणों से, अपीलार्थियों द्वारा दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

17. सी. पी. सी. की धारा 47, जो फरमानों के निष्पादन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है, यह आदेश देती है कि न्यायालय

डिक्री का निष्पादन, डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि के संबंध में मुकदमे के पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का निर्धारण करेगा और यह कि ऐसे प्रश्नों पर एक अलग मुकदमे में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। निष्पादन न्यायालय को अनन्य अधिकारिता प्रदान करने का उद्देश्य अनावश्यक और अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकना और डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि के संबंध में चर्चा के लिए

उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का त्वरित निपटान करना है। क्या कोई प्रतिरोध पेश किया जाना चाहिए या बाधा उत्पन्न की जानी चाहिए

12 (2012) 11 एस. सी. सी. 224 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा दिए गए डिक्री के उचित निष्पादन में बाधा डालते हुए, आदेश XXI के नियम 97, 101 और 98 के प्रावधान निष्पादन अदालत को डिक्री धारक के अंतर-दावों पर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।

और निष्पादन कार्यवाही में तीसरे पक्ष स्वयं पक्षकारों को स्वतंत्र मुकदमे स्थापित करने के लिए प्रेरित करके मुकदमेबाजी के लंबे समय तक चलने से बचने के लिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 97 से 106 में उप-शीर्षक "वितरण के लिए प्रतिरोध" के तहत प्रावधान हैं।

इस न्यायालय ने ब्रह्मदेव चौधरी (उपरोक्त) के साथ-साथ असगर बनाम मोहन वर्मा 1 3 13 में हाल के मूल के निर्णय में डिक्री धारक या खरीदार के कब्जे को अपने आप में एक पूर्ण संहिता माना है। बाद के निर्णय में, यह नोट किया गया है कि आदेश XXI के नियम 97 से 103 दोनों पक्षों के साथ-साथ निष्पादन के लिए रखी गई डिक्री के लिए एक अजनबी के लिए एकमात्र उपाय प्रदान करते हैं।

18. भंवर लाल बनाम सत्यनारायण 1 4 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वह निर्णय से व्युत्पन्न अधिकार का दावा करता हो-देनदार या अपना अधिकार, शीर्षक या ब्याज स्थापित करता है, तो निष्पादन अदालत डिक्री को निष्पादित करते समय, शक्ति के अलावा

नियम 35 (3) के तहत, यह जांच करने का अधिकार है कि क्या उस व्यक्ति द्वारा बाधा कानूनी है या नहीं।

19. नूरुद्दीन बनाम में यह न्यायालय। डॉ. के. एल. आनंद ने दोहराया कि निष्पादन अदालत एक के दावे पर निर्णय लेने के लिए बाध्य थी

बाधा डालने वाला और निष्पादन अदालत के समक्ष रखे गए दावे की अनुमति देने या अस्वीकार करने वाले निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए, व्यक्ति न तो पक्षकार था

पहले की कार्यवाही और न ही उसके खिलाफ डिक्री पारित की जा रही है।

20. एक बार फिर, बाबूलाल बनाम। राज कुमार और अन्य "।, इस न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश को हटाने से पहले आदेश XXI नियम 98 के तहत एक निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

आक्षेपकर्ता द्वारा उत्पन्न बाधा और उस संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि निष्पादन अदालत को उस प्रश्न का निर्धारण करने की आवश्यकता थी जब अपीलकर्ताओं ने उन अपीलार्थियों के खिलाफ डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जताई थी जो विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री के पक्षकार नहीं थे।

21. ब्रह्मदेव चौधरी (ऊपर) में श्री द्वारा उद्धृत निर्णय।

चितमबरेश का भी यही प्रभाव है।

13 (2020) 16 एससीसी 230

1 4 14 (1995) 1 एस. सी. सी 6

15 (1995) 1 एससीसी 242

16 (1996) 3 एस. सी. सी. 154 जीनी धनराजगीर और ए. एन. आर. वी. शिबू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी। [दीपांकर दत्त, जे।]

22. आदेश XXI नियम 97 से 106 की योजना पर विचार करते हुए, यह न्यायालय सिल्वरलाइन फोरम प्राइवेट लिमिटेड में है। लिमिटेड वी. राजीव ट्रस्ट और Anr.¹⁷ ने इसे पाया

उच्च न्यायालय से सहमत होना मुश्किल है कि निष्पादन के लिए दी गई डिक्री के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए प्रतिरोध या बाधा को आदेश XXI नियम 97 के तहत नहीं लिया जा सकता है। नियम 97 से 106 का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाए गए हर प्रकार के प्रतिरोध या बाधा से निपटना था और नियम 97 (2) ने अदालत को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायत पर निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। इस न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की:

" यह स्पष्ट है कि निष्पादन अदालत यह तय कर सकती है कि क्या अवरोधक या अवरोधक डिक्री से बंधा हुआ व्यक्ति है और वह संपत्ति खाली करने से इनकार करता है। यह प्रश्न भी संहिता के आदेश 21, नियम 97 (2) में विचारित न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। न्यायनिर्णयन। इसमें उल्लिखित आवश्यक रूप से एक विस्तृत जांच शामिल नहीं है या

साक्ष्यों का संग्रह। न्यायालय निर्णय दे सकता है

स्वीकार किए गए तथ्यों या यहां तक कि प्रतिरोधक द्वारा किए गए कथनों पर भी। बेशक, अदालत पक्षों को इस तरह के निर्धारण के लिए सबूत पेश करने का निर्देश दे सकती है यदि अदालत इसे आवश्यक समझती है।

23. उदाहरणों की लंबी कतार के बावजूद, यह वास्तव में सच है कि आदेश 21 के नियम 102 के आदेश के संदर्भ में, नियम 98 और 100 उस व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन में प्रतिरोध या बाधा पर लागू नहीं होंगे, जिसे निर्णय-देनदार ने उस मुकदमे की स्थापना के बाद संपत्ति हस्तांतरित की है जिसमें डिक्री पारित की गई थी।

24. श्री दीवान के तर्क का जोर यह रहा है कि प्रत्यर्थी विचाराधीन अल्प अंतरिती हैं, लीस पेंडेंस का सिद्धांत लागू होता है, और नियम 102 की स्पष्ट शर्तों को देखते हुए, आपत्तियां बनाए रखने योग्य नहीं थीं; इसलिए, प्रत्यर्थी नियम 98 के संदर्भ में अपने दावों का निर्णय लेने के संरक्षण के हकदार नहीं हैं।

25. यह तर्क, हालांकि पहली नज़र में आकर्षक है, लेकिन यहाँ प्राप्त होने वाले विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए महत्वहीन हो जाता है। इन से

तथ्यात्मक रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि 1987 में श्रीमती चेरियन द्वारा स्थापित वाद को शुरू में 16 नवंबर 1989 को खारिज कर दिया गया था और 1991 में एक अपील दायर किए जाने पर, 18 दिसंबर 1998 के उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा वाद को निचली अदालत की फाइल में बहाल कर दिया गया था। यदि वास्तव में,

17 (1998) 3 एससीसी 723 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस समय के दौरान मुकदमा खारिज होने के बाद स्थानांतरण हुए हैं जब कोई लंबित याचिका नहीं थी, निष्पादन न्यायालय के लिए यह प्रश्न निर्धारित करना सबसे उपयुक्त होगा कि क्या श्री मैथ्यू द्वारा प्रत्यर्थियों को किए गए किसी भी हस्तांतरण से नियम 102 प्रभावित होगा। इसमें वास्तव में पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व करने का अभ्यास शामिल होगा और केवल इसलिए कि मुकदमे को अंततः 21 अक्टूबर 2000 को घोषित किया गया था और अंततः इस न्यायालय द्वारा मामले में मामूली संशोधन के साथ बरकरार रखा गया था।

मुआवजे की राशि, जो उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को योग्यता से रहित होने के रूप में खारिज करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं होगा।

26. इसके अलावा, भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में श्री मैथ्यू द्वारा प्राप्त खरीद प्रमाण पत्र का प्रभाव जहां श्रीमती चेरियन प्रत्यर्थियों के पक्ष में किए गए स्थानान्तरण पर ध्यान दिया गया था, निष्पादन न्यायालय द्वारा भी जांच की जानी चाहिए। विशेष रूप से, यह उत्तरदाताओं का तर्क है कि उक्त खरीद प्रमाण पत्र के. एल. आर. अधिनियम के संदर्भ में जारी किया गया था और न केवल उसे चुनौती दी गई थी

श्रीमती चेरियन के कहने पर, उन्होंने दीवानी कार्यवाही के किसी भी चरण में इसका कोई खुलासा नहीं किया।

27. उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 अप्रैल 2018 के अप्रत्यासित आदेश को ध्यान में रखते हुए निष्पादन न्यायालय का विवादित आदेश आपत्तियों को बनाए रखने योग्य पाया है, कम से कम एक जांच की आवश्यकता है। तथ्यों पर, इस न्यायालय को इस तरह के आदेश में कोई कानूनी दुर्बलता योग्य नहीं लगती है

हस्तक्षेप। 28. अब इस न्यायालय के 13 अक्टूबर 2014 के आदेश के प्रभाव पर विचार करने का समय आ गया है, जिसके तहत श्री.

थॉमस और श्री अब्राहम को मुआवजे में मामूली राशि बढ़ाने से मना कर दिया गया। सिर्फ इसलिए कि इस न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया

11 फरवरी, 2014 की पहली अपीलीय डिक्री में यह अभिनिर्धारित करने का कोई आधार नहीं है कि ऐसा आदेश नियम 101 द्वारा अनुध्यात प्रकृति की जांच पर रोक लगाएगा। यह न्यायालय 13 अक्टूबर 2014 के आदेश को डिक्री धारकों और अजनबियों/तीसरे पक्षों के बीच विवादों को समाप्त करने के रूप में मानते हुए अपनी दृष्टि को रंगीन नहीं होने देगा। उससे पहले नहीं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय की गरिमा, प्रतिष्ठा और महिमा को बनाए रखना है, फिर भी, केवल इसलिए कि एक ओर अपीलार्थियों और दूसरी ओर श्री थॉमस और श्री अब्राहम के बीच का मुद्दा अंतिम रूप से प्राप्त कर चुका है, लेकिन यह इस न्यायालय के लिए कोई औचित्य नहीं देगा, जो अपीलार्थियों के तर्क को बनाए रखने के लिए बहुत कम पर्याप्त औचित्य है, जो आदेश जीनी धनराजगीर और ए. एन. आर. के नियम 97 से 103 के मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के बजाय नष्ट करने का प्रभाव रखता है।

वी. शिवू मैथ्यू और ए. एन. आर. ईटीसी। [दीपांकर दत्त, जे।]

XXI उन अजनबियों/तीसरे पक्षों को प्रदान करता है जो कब्जे की वसूली के लिए डिक्री से बाध्य नहीं हैं। डिक्रीटल संपत्ति में उनके संबंधित शेयरों के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज के बारे में दावा, जैसा कि द्वारा उठाया गया है

उत्तरदाताओं को, सीमा पर बाहर नहीं फेंका जा सकता क्योंकि यह अच्छी तरह से भीतर है

अपीलार्थियों द्वारा दायर आदेश XXI नियम 97, सी. पी. सी. के तहत आवेदन को चुनौती देने के उनके अधिकार। चूंकि उसके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, इसलिए निष्पादन न्यायालय इस स्तर पर आपत्तियों को बनाए रखने योग्य ठहराने के लिए इस अर्थ में न्यायोचित था कि उनके खिलाफ डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस अर्थ में कि एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था ताकि जांच की जा सके और पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के लिए मामले को पोस्ट किया जा सके। हमें विश्वास है कि नियम 101 में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर, निष्पादन न्यायालय नियम 98 द्वारा अनिवार्य तरीके से आगे बढ़ेगा।

29. इसके अलावा, श्री चितमबरेश सही हैं जब वे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय को आदेश के खिलाफ उपरोक्त अपीलों पर विचार नहीं करना चाहिए ऐसे आदेश के बिना न्यायालय का निष्पादन उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा किसी भी चुनौती के अधीन किया गया है। श्री द्वारा उद्धृत निर्णय में।

चितमबरेश, अर्थात्, , आई. टी. आई. लिमिटेड (ऊपर), यह देखा गया कि वादियों को त्वरित और अधिक प्रभावी उपचार की तुलना में बिना किसी बेहतर कारण के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए कूदना, छोड़ना और कूदना नहीं चाहिए। व्यवहार के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर न्यायाधिकरणों/न्यायालयों के आदेशों से सीधे विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करता है, बिना उच्च न्यायालय से केवल उन मामलों में संपर्क किया गया है जहां सामान्य महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं या जहां इसी तरह का कोई मुद्दा उसके (सर्वोच्च न्यायालय के) विचार के लिए लंबित है। निर्णय में

कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर कंपनी (ऊपर) इस आशय की है। हालाँकि, ये ऐसे मामले हैं जो बहुत कम हैं। देने की शक्ति अनुच्छेद 136 के तहत स्वतः विवेकाधीन होने के कारण, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के स्तर पर उपलब्ध उपचार को दरकिनार करने के लिए 'विशेष अनुमति' अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष को उपरोक्त दो स्थितियों को संतुष्ट किए बिना अनुमति नहीं देगा। वास्तव में, यह ऐसा कोई मामला नहीं है।

31. यह स्पष्ट किया जाता है कि निष्पादन न्यायालय आदेश XXI के नियम 97 के तहत अपीलार्थियों के आवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा। सी. पी. सी. उत्तरदाताओं द्वारा अपने गुण-दोष पर और [2023] 5 एस. सी. आर. में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना उठाई गई आपत्तियों के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह आदेश जो केवल वर्तमान के निपटान के लिए आवश्यक है

32. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी दो दशकों से अधिक समय से 21 अक्टूबर 2000 के फरमान के फल से वंचित हैं, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना विवादास्पद मुद्दों पर कानून के अनुसार जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए निष्पादन न्यायालय से अनुरोध करना उचित और उचित होगा। इस प्रकार यह विशेष रूप से वांछनीय होगा यदि इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 18 महीने के भीतर कार्यवाही पूरी कर ली जाए। और आदेश दें।

33. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, अवमानना याचिका (सी) सं. 2091/2018 श्री थॉमस और श्री थॉमस को दंडित करने के लिए अपीलार्थियों द्वारा शुरू की गई। इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या में पारित 13 अक्टूबर, 2014 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अब्राहम। इसलिए, वही पद खारिज कर दिया जाता है।

याचिका और अवमानना याचिका

खारिज कर दी गई।

निधि जैन (सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)